

राष्ट्रमंडेरियल का ट्रेंड देखें, फिर मार्केट तलाश करें, इसके बाद लगाए यूनित

मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और एसोसिएम के सहयोग से हुई एग्री एंड फूड प्रोसेसर कॉन्क्लव में एक्सपर्ट ने दी जानकारी

AGRO CONCLAVE

सिटी रियल्टी • अगर आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाना चाहते हैं तो इसके लिए संबंधित क्षेत्र में राॅ मंडेरियल का ट्रेंड जानना होगा। क्षेत्र की जरूरत क्या है और इंडस्ट्री की जरूरत कैसे पूरी होगी। आप किस चीज का उत्पादन करना चाहते हैं, पहले वो मार्केट तलाश फिर यूनिट लगाने की शुरुआत करें। इस तरह फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यह बात एक्सपर्ट ने कही। सोमवार को मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज और ए एसोसिएम के वेंचर्स ऑफ कॉर्पोरेशन एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसोसिएम) के संयुक्त तत्वावधान में एग्रीकल्चर कॉन्क्लव के सभागार में एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कॉन्क्लव कराई गई। एक्सपर्ट ने कहा कि जो भी यूनिट लगाएं उसका एकीकृतेशन जरूर कराएं। इससे आसानी आतामिश्रवास बढ़ेगा।

लोकल मार्केटिंग प्रोग्राम से मिलेगा फायदा

एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. एके सिंह ने कहा कि मग्न को 11 एग्री क्लाइंट डिवीजन में भी रखा गया है। हमें फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए लोकल मार्केटिंग प्रोग्राम विकसित करना होगा। इससे फायदा यह होगा कि उत्पादन अच्छे स्तर का होगा और उपभोक्ताओं को सही दामों में वस्तु मिल सकेगी।



• एक्सपर्ट ने कहा कि मग्न में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए भी है कि मक इस इंडिया की तरफ पर मक इस मग्न अभियान चलाया जा रहा है।

ऑनलाइन पोर्टल से जानें

एसबीआई के एजीएम अखंडराय चंद्र सक्सेना ने कहा कि डायरेक्टर-सहकार संस्था में एग्री फूड प्रोसेसिंग में स्मॉल एग्रीकल्चर जल्दी है। जो लोग इस क्षेत्र में आना चाहते हैं उनकी सहाय्यता के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है। इस पर अखंडराय सक्सेना के साथ यह बात करते हैं कि प्रक्रिया कहां तक पूरी हुई है।

यह भी बताया

क्यासिटी काउंसिलर और इंडिया के 4 नेबरल एकीकृतेशन बोर्ड फॉर सॉलिकेकेशन वॉशिंग (एनएबीसी) के एक्सपर्ट उदय कुमार सक्सेना ने कहा कि एनएबीसी कई तरह के एकीकृतेशन ऑफर करता है। इसमें फूड सेप्टी मेंबरमेंट, प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन सहित अन्य शामिल हैं। जानकारी www.gocl.org से ले सकते हैं।

यह भी रखें

• एग्रीकल्चर रिजर्व और एक्सटेंशन शीटिंगिडि हो।
• शांतिपुत्रा इलाकों में शिकरी कर्टसी कम करली होगी।
• सिडोई इन्वेस्टर्स हैं लोकल शांतिपुत्रा इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्टर करना होगा।
• मंडी स्तर से हमें गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है।

प्रदेश में बेहतर संभावनाएं

डिप्टी कमिश्नर शिवांग भांगव ने कहा कि प्रदेश में 6 सरकारी मंडी फूड पार्क और 2 प्राइवेट फूड पार्क हैं। इसलिए यहां फूड प्रोसेसिंग में बेहतर संभावनाएं हैं। साथ ही युवाओं को क्यासिटी ट्रेनिंग और नई एग्री टेक्नोलॉजी के जरिए उत्पादन क्षमता भी बढ़ानी होगी।

सरकार ने दिष्ट 2 हजार करोड़

नाबाई के अतिस्टेट जनरल मैनेजर संजीव रमल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 2 हजार करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इससे जो लोग आसानी कर सकते हैं, जो फूड पार्क में यूनिट लगाते जा रहे हैं।

यह रहे मौजूद: कार्यकम के मुख्य आतिथि राजभागा विजयापटो सिधिया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. एके सिंह थे। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शिवांग भांगव, एग्रीकल्चर कॉन्सेज के डीन डॉ. जेपी श्रीवास्तव, जवाइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर राजीव जोशी, एसोसिएम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा दीबा, सेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशन के जानसेनी सावित्रा डॉ. प्रवीण अय्यंगर, डॉ. प्रमोद परतल, डॉ. सुरेश सिंह तीव्र, क्यासिटी काउंसिलर और इंडिया के उदय कुमार सक्सेना और डॉ. सुधीर चतुर्वेदी मौजूद रहे।

एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कॉन्क्लेव आयोजित

मेक इन मप्र से किसानों को होगा फायदा

पत्रिका PLUS रिपोर्ट

ग्वालियर • सोयाबीन उत्पादन के कारण ही मध्यप्रदेश सोया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दलहन उत्पादन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है जो कि न्यूट्रिशनल सिक्वोरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्यप्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा विकास का रोड मैप तैयार करते हुए भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर मेक इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह बात मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अनिल कुमार सिंह ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही। मौका था खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार और राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित एग्री एंड फूड



प्रोसेसर्स कॉन्क्लेव का। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डिप्टी कमिश्नर विनोद भार्गव रहे।

किसानों में बढ़ेगा आत्मविश्वास : कार्यक्रम में कुलपति प्रो. सिंह ने आज के आधुनिक परिदृश्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत गांवों का देश है जिसकी अर्थव्यवस्था का मूल आधार

कृषि है। यदि समुचित महत्व दिया जाए तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग ग्रामीण आत्मनिर्भरता एवं रोजगार सृजन के मामले में परिवर्तन का कारण बन सकता है। गांव-शहर की खाई को पाट सकता है और किसानों के तौर-तरीकों में सुधार लाया जा सकता है। कार्यक्रम में एसोचेम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा ढींगर ने वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की जानकारी देते हुए एसोचेम

द्वारा इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। इस बैठक में तकनीकी सेशनल का आयोजन किया गया। जिसमें लगभग 200 से अधिक खाद्य प्रसंस्करण एवं तकनीकी, कृषि एवं उद्यानिकी विकास, बैंकिंग, नाबार्ड, मप्र चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री, खाद्य भंडारण चेन से जुड़ी संस्थानों, विभागों एवं उद्यमियों, वैज्ञानिकों आदि ने हिस्सा लिया।

खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ें किसान : सिंह

ग्वालियर, 30 जनवरी, नभासं. राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, एसोचेम एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विश्वविद्यालय में "एग्री एण्ड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव" वित्त, तकनीकी एवं बाजार विषय पर एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रो. अनिल कुमार सिंह, कुलपति,

रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर थे। इसके अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद भार्गव, डिप्टी कमिश्नर तथा इस अवसर पर राजीव जोशी, संयुक्त संचालक, डॉ. प्रवीण अग्रवाल, सचिव, म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, अवधेशचन्द्र सक्सेना, ए.जी.एम. भारतीय स्टेट बैंक, कु. पूर्णिमा ढोंगरा, डिप्टी डायरेक्टर, एसोचेम, नई दिल्ली, डॉ. जे.पी. दीक्षित, अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर एवं डॉ.एम.एम.पटेल अयोजन सचिव एवं विभागाध्यक्ष विस्तार शिक्षा विभाग कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर उपस्थित थे। कु. पूर्णिमा



ढोंगरा, डिप्टी डायरेक्टर, एसोचेम, नई दिल्ली द्वारा वर्तमान परिदृश्य में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति की जानकारी देते हुए एसोचेम द्वारा इस दिशा में किये जा रहे प्रयासों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई।

मुख्य अतिथि प्रो. अनिल कुमार सिंह ने आज के आधुनिक परिदृश्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका पर प्रकाश डाला तथा कृषकों को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ने की सलाह दी। आपके द्वारा जानकारी दी गई कि सोयाबीन उत्पादन के

कारण मध्यप्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है इसी के साथ दलहन उत्पादन में भी मध्यप्रदेश अग्रणी है जो कि न्यूट्रीशनल सिक्योरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। मध्य प्रदेश पासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा आर्थिक विकास का रोड मैप तैयार करते हुये भारत सरकार के 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम की तर्ज पर 'मेक इन मध्य प्रदेश' कार्यक्रम की

पुरूआत की गई। उक्त बैठक में तकनीकी सत्र का भी आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता डॉ. सुरेश सिंह तोमर, अधिष्ठाता कृषि सकाय, रा.वि.सिं.कृ.वि.वि., ग्वालियर ने की। इस बैठक में लगभग २०० से अधिक खाद्य प्रसंस्करण एवं तकनीकी, कृषि एवं उद्योगिकी विकास, बैंकिंग, नाबार्ड, म.प्र. चेम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इण्डस्ट्री, खाद्य भंडारण चेन से जुड़ी संस्थाओं, विभागों एवं उद्यमियों, वैज्ञानिक, प्राध्यापक, छात्रों एवं कृषकों ने भागीदारी सुनिश्चित की।

आयोजन ▶ एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव वित्त तकनीकी एवं बाजार विषय पर कार्यक्रम संपन्न प्रदेश न्यूट्रीशनल सिक्युरिटी की भूमिका निभा रहा है: प्रो. सिंह

पीपुल्स संवाददाता • ग्वालियर
editor@peoplesamachar.co.in

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को एग्री एंड फूड प्रोसेसर्स कोन्क्लेव वित्त तकनीकी एवं बाजार विषय पर कार्यक्रम आयोजित हुआ।

विवि के कुलपति प्रो. एके सिंह ने आधुनिक परिदृश्य में कृषकों की आय बढ़ाने में खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन की भूमिका पर प्रकाश डाला



तथा कृषकों को खाद्य एवं प्रसंस्करण उद्योगों से जुड़ने की सलाह दी। प्रो. सिंह ने कहा कि सोयाबीन उत्पादन के कारण मध्यप्रदेश सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, दलहन उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है जो कि

न्यूट्रीशनल सिक्युरिटी में एक अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश शासन द्वारा खाद्य प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, देश का प्रथम राज्य है जिसके द्वारा आर्थिक विकास

का रोड मैप तैयार करते हुए भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तर्ज पर मेक इन मध्यप्रदेश कार्यक्रम की शुरुआत की गई। एसोचेम की डिप्टी डायरेक्टर पूर्णिमा ढोंगरा ने वर्तमान परिदृश्य में खाद्य

प्रसंस्करण की स्थिति व एसोचेम द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में विनोद भागवत डिप्टी कमिश्नर ग्वालियर संभाग, राजीव जोशी, संयुक्त संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. शासन, डॉ. प्रवीण अग्रवाल सचिव म.प्र. चेंबर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, अवधेशचंद्र सक्सेना एजीएम भारतीय स्टेट बैंक ग्वालियर, डॉ. जेपी दीक्षित अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय ग्वालियर एवं डॉ. एमएम पटेल अयोजन सचिव व विभागाध्यक्ष विस्तार शिक्षा विभाग कृषि महाविद्यालय, ग्वालियर उपस्थित थे।

